NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

दैनिक समाचार विश्लेषण

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Monday, 22 Sep, 2025

Edition : InternationalTable of Contents

Page 01 **Syllabus :GS 2 : International Relations/ Prelims**	नएआवेदकोंकेलिए एकमुश्त एच-1बी शुल्क: यू.एस.
Page 04 **Syllabus :Prelims**	भारतीयवायुसेनाकादिग्गज विमान मिग-21 छह दशक की सेवा के बाद 26 सितंबर को सूर्यास्त केलिएउड़ानभरेगा
Page 06 **Syllabus :GS 2 : Indian Polity / Prelims**	'हमबड़ेउद्योगोंसे डरते हैं; बाहरी लोग हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे'
Page 07 **Syllabus :GS 3 : Science and tech / Prelims**	खगोलविदोंनेबिगबैंग के बाद से सबसे बड़े धमाके देखे हैं
Page 08 **Syllabus :GS 2 : International Relations / Prelims**	एच-1बी विमान, शायद: भारत के तकनीकी कर्मचारियों को अमेरिकी नौकरियों पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए
Page 10 : Editorial Analysis **Syllabus :GS 2 : Indian Polity**	क्याराज्यपालोंकेलिए समयसीमा तय की जा सकती है?

दैनिक समाचार विश्लेषण

Page 01 : GS 2 : International Relations/ Prelims

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी सरकार ने हाल ही में **एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाकर 100,000 डॉलर करने की** घोषणा की थी। प्रारंभ में, भ्रम की स्थिति बनी हुई क्योंकि वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने सुझाव दिया कि यह एक *वार्षिक* शुल्क होगा। हालांकि, व्हाइट हाउस ने बाद में स्पष्ट किया कि यह अगले **लॉटरी चक्र से शुरू होने वाले नए एच-1बी आवेदकों के लिए एक बार का शुल्क होगा**। इस स्पष्टीकरण से विदेशों में भारतीय एच-1बी वीजाधारकों में घबराहट कम हो गई है, जो भारी शुल्क के डर से अंतिम समय में उड़ानों की बुकिंग के लिए पहुंचे थे।

One-time H-1B fee for new applicants: U.S.

- Only fresh H-1B visa applicants will have to pay starting with the 'next upcoming lottery cycle'
- Announcement eased fears among NRIs that triggered surge in flight bookings to the U.S.
- Lutnick had stated that no more would these giant tech companies train foreign workers

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

A day after U.S. President Donald Trump hiked H-1B visa fees to $100,000, the White House clarified that the fee will not be an annual feature, but rather a "one-time" payment that will have to be made by companies for fresh H-1B visa applicants, starting with the "next upcoming lottery cycle".

The announcement eased the fears that had triggered a surge in last-minute flight bookings to the United States by Indian H-1B visa holders who are currently outside the country, after U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick's earlier remarks indicating that the fee amount would have to be paid every year. However, White House Press Secretary Karoline Leavitt contradicted the Commerce Secretary's comments in a social media post early on Sunday.

"To be clear: this is not an annual fee. It's a one-time fee that applies only to the petition. Those who already hold H-1B visas and are currently outside of the country right now will not be charged $100,000 to re-enter. H-1B visa holders can leave and re-enter the country to the same extent as they normally would: whatever ability they have to do that is not impacted by yesterday's proclamation," the Press Secretary said.

"This applies only to new visas, not renewals and not current visa holders. It will first apply in the next upcoming lottery cycle," she added.

Clarity emerges

The White House issued a clarification after an initial announcement on the H-1B visa fee led to panic

- The $100,000 fee will be a 'one-time' payment
- The fee applies only to new applicants. Those applying for renewals or current visa holders need not make the payment
- U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick had initially said that the fee would be applied annually, leading to much of the confusion

Lutnick's remarks

During the signing of the proclamation by Mr. Trump, Mr. Lutnick had said, "No more will these big tech companies train foreign workers. They have to pay the government a hundred thousand dollars and then they have to pay the employee. So it's just non-economical. If you are going to train somebody, you are going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land."

He added, "A hundred thousand dollars a year for H-1B visas and all of the big companies are onboard."

Rush for tickets

In its first response on September 20, the Ministry of External Affairs had cautioned that the order would have "humanitarian consequences" due to family disruptions.

Soon after the proclamation by Mr. Trump, several corporate giants, including Microsoft, JPMorgan and Amazon, instructed their H-1B visa holding employees who were outside the U.S. to return before midnight on Saturday, telling others to remain in the U.S.

Mr. Lutnick's remarks created a rush among H-1B visa holders for last minute purchases of air tickets.

The Hindu reported on Sunday that travel agents observed a surge in last-minute flight bookings to the U.S. on Saturday as H-1B visa holders attempted to reach their work stations in the U.S. ahead of the September 20-21 midnight deadline when the proclamation came into effect.

Officials also observed the spike in last-minute flight bookings, following which the Indian government instructed its missions and embassies across the world to provide "all possible help" to Indians trying to return to the U.S. before the deadline.

Opposition decry failure to take a strong stand

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Opposition on Sunday took a swipe at Prime Minister Narendra Modi for not taking a firm stand against the "strong-arm tactics" of the U.S. and instead adopting an "escapist approach" by giving "vague sermons" about self-reliance. They targeted the PM over U.S. President Trump's move to impose a fee of $100,000 for H-1B visas.

FULL REPORT ON » PAGE 5

स्थैतिक पृष्ठभूमि

1. **एच-1बी वीजा क्या है?**
   - एक गैर-आप्रवासी अमेरिकी वीजा जो कंपनियों को तकनीकी या सैद्धांतिक विशेषज्ञता (जैसे, आईटी, इंजीनियरिंग, वित्त, अनुसंधान) की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियोजित करने की अनुमति देता है।
   - वैधता: शुरू में 3 साल, 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
2. **भारत-अमेरिका संबंध**
   - **एच-1बी वीजा का लगभग 70%** भारतीय पेशेवरों को जाता है, विशेष रूप से आईटी क्षेत्र (इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, आदि) में।
   - प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सेवाओं में भारत और अमेरिका के बीच **एक रणनीतिक पुल** के रूप में कार्य करता है।
3. **ऐतिहासिक संदर्भ**
   - एच -1 बी पर अमेरिकी बहस अक्सर **घरेलू नौकरी की सुरक्षा बनाम वैश्विक प्रतिभा की आवश्यकता** के इयाद घूमती है।

- इसी तरह के विवाद ट्रम्प के 2017 के "अमेरिकी खरीदें, अमेरिकी को किराए पर लें" कार्यकारी आदेश के दौरान हुए थे।

वर्तमान विकास

- **शुल्क वृद्धि:** केवल नए आवेदकों *पर* $100,000 *एकमुश्त शुल्क*।
- **इस पर कोई प्रभाव नहीं:** वर्तमान एच-1बी वीजा धारक या नवीनीकरण।
- **भ्रम:** लुटनिककीटिप्पणीनेदहशतपैदाकरदीकियहवार्षिकहोगा।
- **स्पष्टीकरण:** व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि यह पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।
- **तत्काल परिणाम:**
  - विदेशों में एच-1बी धारकों द्वारा अंतिम क्षणों में उड़ान बुकिंग में अचानक वृद्धि।
  - भारतीय विदेश मंत्रालय ने **पारिवारिक व्यवधानों के कारण** मानवीय चिंताओं को व्यक्त किया।
  - माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन और अमेज़ॅन जैसी कंपनियों ने कर्मचारियों को समय सीमा से पहले अमेरिका वापस जाने की सलाह दी।

मुख्य निहितार्थ

1. **भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए**
   - नियोक्ताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा →भारतीयोंकीनियुक्तिमेंकमीआएगी।
   - इससे कंपनियां निकटवर्ती केंद्रों (कनाडा, मेक्सिको) या दूरस्थ कार्य मॉडल की ओर रुख कर सकती हैं।
2. **भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए**
   - आईटी निर्यात (~ $ 250 बिलियन क्षेत्र) मंदी का सामना कर सकता है।
   - अगर कम एच-1बी वीजा जारी किए जाते हैं तो अमेरिका (भारत के लिए सबसे बड़ा स्रोत देश) से प्रेषण कम हो सकता है।
3. **अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए**
   - भारतीय प्रतिभा पर निर्भर तकनीकी उद्योग को प्रतिभा की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
   - नवाचार की लागत बढ़ सकती है और प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकती है।
4. **राजनयिक कोण**
   - भारत ने द्विपक्षीय वार्ता में **वीजा प्रतिबंधों** पर लगातार चिंता जताई है।
   - भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी **में एक महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता** है, भले ही रक्षा और व्यापार संबंध बढ़ रहे हों।
5. **सामाजिक और मानवीय चिंताएं**
   - अचानक आदेश के कारण पारिवारिक व्यवधान।
   - एनआरआई समुदाय में चिंता।

आगे की राह

- **भारत के लिए:**
  - आईटी बाजारों (यूरोप, आसियान, अफ्रीका) में विविधता लाएं।
  - डब्ल्यूटीओ वार्ताओं में मोड 4 उदारीकरण **(प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही)** पर जोर देना।
  - विदेशी बाजारों पर निर्भरता कम करने के लिए **घरेलू उच्च तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र** में निवेश करें।
- **अमेरिका के लिए:**
  - घरेलू नौकरियों की रक्षा करने और नवाचार में बढ़त बनाए रखने के बीच संतुलन।
  - अचानक घोषणाओं के बजाय संरचित वीजा नीति।

दैनिक समाचार विश्लेषण

निष्कर्ष

100,000 डॉलर का एकमुश्त एच-1बी वीजा शुल्क **लगाने का अमेरिका का फैसला** घरेलू राजनीतिक मजबूरियों और वैश्विक प्रतिभा की जरूरतों **के बीच लगातार तनाव को उजागर करता** है। भारत के लिए, यह अपनी **घरेलू नवाचार क्षमता को मजबूत करने** और आईटी निर्यात के लिए एच-1बी वीजा पर निर्भरता को कम करने के लिए एक अनुस्मारक है। हालांकि स्पष्टीकरण ने तत्काल घबराहट को कम कर दिया है, लेकिन यह घटनाक्रम इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे वीजा नीति **भारत-अमेरिका संबंधों में एक रणनीतिक और आर्थिक चर बनी हुई है**।

UPSC Prelims Practice Questio

प्रश्न: एच-1बी वीजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक अमेरिकी आप्रवासी वीजा है जो कुशल श्रमिकों के लिए स्थायी निवास की अनुमति देता है।

2. वीज़ा शुरू में 3 साल के लिए वैध होता है और इसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

3. अधिकांश एच-1बी वीजा भारत के पेशेवरों को जारी किए जाते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) तीनों

(d) कोई नहीं

उत्तर: (b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत के आईटी उद्योग और विदेशी मुद्रा आय पर अमेरिकी एच-1बी वीजा शुल्क वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन करें। एच-1बी वीजा पर निर्भरता कम करने के लिए भारत क्या उपाय कर सकता है? **(250 शब्द)**

Page 04 :Prelims

26 सितंबर, 2025 **को**, **भारतीय वायु सेना (IAF)** लगभग 62 वर्षों की सेवा **के बाद अपने पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट** मिग-21 **को औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त कर देगी**। **भारतीय वायु रक्षा के "वर्कहॉर्स"** के रूप में जाना जाता है, मिग -21 ने न केवल युद्ध और संघर्ष लड़ा, बल्कि भारत की बढ़ती एयरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं का भी प्रतीक था। इसे शामिल नहीं करना एक युग के अंत का प्रतीक है और बढ़ती क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के समय भारत की लड़ाकू ताकत परसवालउठाताहै।

IAF's legendary workhorse MiG-21 to fly into sunset on Sept. 26 after six decades of service

Saurabh Trivedi
NEW DELHI

The Indian Air Force will officially retire its legendary MiG-21 fighter jets on September 26, marking the end of nearly six decades of service for the aircraft widely hailed as the "workhorse" of India's air defence.

A ceremonial flypast and decommissioning event will be held at the IAF base in Chandigarh and will be attended by senior military leaders and veteran pilots who have flown the jet across generations.

Glorious stint: Air Chief Marshal A.P. Singh flew the aircraft recently ahead of its official retirement. FILE PHOTO

Inducted in 1963, the MiG-21 was India's first supersonic fighter, with its maiden squadron – the 28 Squadron at Chandigarh – earning the nickname 'First Supersonics'. Over the years, India inducted more than 700 MiG-21s of different variants, many built domestically by the Hindustan Aeronautics Limited.

The aircraft was the backbone of the IAF till the mid-2000s, playing crucial roles in the 1965 and 1971 wars, the 1999 Kargil conflict, the 2019 Balakot air strikes, and most recently Operation Sindoor. It was in a MiG-21 that Group Captain Abhinandan Varthaman (then Wing Commander) shot down a Pakistani F-16 in 2019 before being captured across the border. Besides combat successes, the MiG-21 also boosted India's aerospace industry, pushing indigenous manufacturing and technological capabilities to new levels.

The IAF, in a post on X, described the MiG-21 as a "warhorse that carried the pride of a nation into the skies" and released a tribute video showcasing its storied history.

As the MiG-21 squadrons are phased out, the IAF's combat strength will dip to 29 squadrons.

स्थैतिक पृष्ठभूमि

- **प्रेरण:** 1963; पहला स्क्वाड्रन = 28 *स्क्वाड्रन, चंडीगढ़* → "प्रथम सुपरसोनिक्स"।
- **संख्या:** भारत ने **700 से अधिक मिग -21** (विभिन्न संस्करण, कई एचएएल द्वारा निर्मित) शामिल किए।
- **युद्ध और अभियान:**
  - 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध→में निर्णायक भूमिका निभाई।
  - 1999 कारगिलसंघर्ष।

- 2019 बालाकोट हवाई हमला और हवाई डॉगफाइट→ अभिनंदनवर्धमाननेपाकिस्तानीएफ -16 कोमारगिरायाथा।
- 2023 "ऑपरेशन सिंदूर" (नवीनतमलड़ाकूभूमिका)।

- **उद्योग में योगदान:** एचएएल और स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमता **को मजबूत करना**।
- **उपनाम:** "वर्कहॉर्स", "फर्स्ट सुपरसोनिक्स", "वॉरहॉर्स जिसने एक राष्ट्र के गौरव को आसमान मेंलेलिया" ।

वर्तमान विकास (2025)

- **सेरेमोनियल रिटायरमेंट:** 26 सितंबर, 2025, आईएएफ बेस चंडीगढ़।
- एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, पूर्व सैनिक, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
- **प्रतीकात्मक अंतिम उड़ान:** अपनी 60+ वर्षों की सेवा को प्रदर्शित करनेवालाएकफ्लाईपास्ट।
- **सेवानिवृत्ति के बाद IAF का दर्जा:** लड़ाकू ताकत 29 स्क्वाड्रन **(स्वीकृत 42 से नीचे)** तक गिर जाती है।

प्रभाव

1. **परिचालन अंतर**
   - सेवानिवृत्ति दो मोर्चों वाले खतरे (चीन और पाकिस्तान) के खिलाफ स्क्वाड्रन की ताकत → क्षमता की चुनौती को कम करती है।
   - Su-30 MKI, राफेल, तेजस, मिराज-2000 **पर अधिक निर्भरता**।
2. **स्वदेशीकरणकोबढ़ावादेना**
   - एलसीए तेजस एमके-1ए,एएमसीए **और विदेशी सहयोग** को तेजी से शामिल करने के लिए जगह खोलती है।
   - रक्षाक्षेत्रमें *आत्मनिर्भरभारत*कोबढ़ावा
3. **ऐतिहासिक विरासत**
   - यह यूएसएसआर के साथ भारत के शीत युद्ध के समय के रक्षा संबंधोंकाप्रतीकहै।
   - भारत को वर्तमान एयरोस्पेस उद्योग की नींव → **एचएएल की लाइसेंस प्राप्त उत्पादन** क्षमताओं को विकसित करने में मदद की।
4. **रणनीतिक चिंताएँ**
   - पाकिस्तान अभी भी जेएफ-17 (चीन-पाक को-प्रोडक्शन) का संचालन करता है।
   - चीन ने 5वीं पीढ़ी के जेट (J-20) को उन्नत किया है।
   - भारत के बेड़े को युक्तिसंगत बनाना और नए अधिग्रहण (तेजस, एमआरएफए सौदा) जरूरीहोगएहैं।
5. **जन भावना**
   - भावनात्मक जुड़ाव: भारतीय वायुसेना के पायलटों की पीढ़ियों ने मिग-21 में प्रशिक्षण लिया और लड़ाई लड़ी।
   - सुरक्षा चिंताओं (बाद के वर्षों में उच्च दुर्घटना रिकॉर्ड) से भी जुड़ा हुआ है।

आगे की राह

- तेजस एमके-1ए, तेजस एमके-2, राफेल-एम, एएमसीए**कोतेजीसेशामिलकियाजाएगा**।
- स्वीकृत 42 की ओर **स्क्वाड्रन संख्या** को मजबूत करना।
- निजी क्षेत्र के साथ घरेलू विनिर्माण **में निवेश** + डीआरडीओ-एचएएल तालमेल
- उन्नत लड़ाकू विमानों के लिए संतुलित विदेशी साझेदारी (फ्रांस, रूस, अमेरिका) **बनाए रखें**।

निष्कर्ष

मिग-21 के सेवानिवृत्त होने से भारतीय वायु शक्ति में एक ऐतिहासिक अध्याय बंद हो गया है। 1965 के युद्ध से लेकर 2019 के बालाकोट हवाई डॉगफाइट तक, यह **भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शक्ति की स्टील रीढ़** थी। हालांकि, इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त

करने से बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच अपने बेड़े को आधुनिक बनाने की भारत की तत्काल आवश्यकता उजागर हो गई है। मिग-21 की विरासत सिर्फ आसमान में मिली जीत में ही नहीं है, बल्कि **इसने भारत की आत्मनिर्भर एयरोस्पेस यात्रा** की नींव कैसे रखी, इसमें भी है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: मिग-21 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारतीय वायु सेना द्वारा शामिल किया गया पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था।

2. मिग-21 का पहला स्क्वाड्रन अंबाला में स्थित था और इसे "फर्स्ट सुपरसोनिक्स" कहा जाता था।

3. ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने 2019 बालाकोट हवाई झड़प के दौरान मिग-21 उड़ायाथा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

Page 06 :GS 2 : Indian Polity / Prelims

2019 में जम्मू और कश्मीर से अलग हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह एपेक्सबॉडी (एलएबी)**और**कारगिलडेमोक्रेटिकअलायंस (केडीए)**जैसेस्थानीयनिकायोंकेनेतृत्वमेंबार-बारविरोधप्रदर्शनऔरभूखहड़तालदेखीगईहै**। उनकीमांगें-**राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची को शामिल करना, लेह और कारगिल के लिए अलग-अलग लोकसभा सीटें और सरकारी रिक्तियों को भरना**-रणनीतिक राष्ट्रीय हितों **और** भूमि, नौकरियों और संस्कृति पर सुरक्षा की स्थानीय आकांक्षाओं **के बीच तनाव को उजागर करती हैं**.

'We fear big industries; outsiders will occupy our land'

The ongoing protest in Ladakh is for Statehood, Sixth Schedule safeguards, Lok Sabha seats for Leh, Kargil, filling of job vacancies, says president of Ladakh Buddhist Association and co-convener of Leh Apex Body; he says their primary complaint is that talks are not taking place on a regular basis

INTERVIEW

Cherring Dorjay Lakruk

Vijaita Singh
NEW DELHI

Climate activist Sonam Wangchuk and other residents of Ladakh are on a hunger strike to demand constitutional safeguards for the region bordering China that was converted into a Union Territory in 2019. A high-powered committee (HPC) led by Minister of State for Home Nityanand Rai was constituted in January 2023 to address the concerns of people in Ladakh. The committee was reconstituted in November 2023, but the talks broke down in March 2024. The discussions resumed on December 3, 2024, and the last round was held on May 27. Cherring Dorjay Lakruk, the president of the powerful Ladakh Buddhist Association and co-convener of the Leh Apex Body, which is part of the HPC, speaks about their protest.

Why are you protesting again?

This is essentially for our four demands [inclusion in the Sixth Schedule of the Constitution (tribal status), Statehood, separate Lok Sabha seats for Leh and Kargil districts, and filling of existing government vacancies]. The Home Ministry has suspended the talks, and it is being done to resume the process.

How long will it go on?

Mr. Wangchuk has declared that the protest and the hunger strike will go on for 35 days. However, this could be extended.

How many meetings did you have with the Home Ministry so far?

For the past four or five years, we have had many rounds of talks, but those have been irregular. Last year, Sonam Wangchuk had to march from Leh to Delhi and sit on a hunger strike, only then the talks resumed. Our primary complaint is that the talks are not taking place on a regular basis.

In May, President Droupadi Murmu notified four regulations for Ladakh, defining new policies on reservation, languages, domiciles, and composition of hill councils. Didn't these incorporate your demands?

No, talks have taken place pertaining to our two major demands - Statehood and Sixth Schedule.

When Ladakh became a Union Territory, there were celebrations in Leh by the BJP. You have been associated with it.

I was in BJP then, but did not celebrate. Our main demand then was U.T. with legislature.

Has the Home Ministry ever assured Statehood in the talks so far?

They said they will discuss, but the provision for Statehood is there in the Constitution.

What are the changes you expect if Statehood is granted?

Our main concern is land. This is a lot of barren land here. Safeguarding land is our priority. Jobs and culture can be protected by the Sixth Schedule.

What is the fear around land?

We fear big industries and hotels will come here and outsiders will occupy our land. Here, hotels are run by family businesses; we do not have 400-500 room hotels here. Outsiders will take away our businesses.

What kind of protection you had when you were part of J&K?

Our land was 100% protected then. No outsiders could apply for jobs. Because of Article 370, outsiders could not buy land. Now they can.

What will be your next move?

The Ministry has sent us feelers for talks. It wants us to end the fast, but we cannot call off the strike. If the talks go in the right direction, we can consider. We won't suspend the hunger strike.

दैनिक समाचार विश्लेषण

वर्तमान संदर्भ

- **विरोध प्रदर्शन:** जलवायु कार्यकर्ता **सोनम वांगचुक** और नागरिक समाज के नेता **संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर** भूख हड़ताल (35 दिनों की योजना, बढ़ सकती है) पर हैं।
- **केंद्र के साथ वार्ता:** गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के तहत 2023 में एक **उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC)** का गठन किया गया था। बातचीत अनियमित रही है, मार्च 2024 में टूट गई और दिसंबर 2024-मई 2025 में कुछ समय के लिए फिरसेशुरूहुई।
- **चिंताओं:**
  - बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने और बड़े उद्योग/होटल स्थापितकरने का डर।
  - गृह मंत्रालय के साथ नियमित बातचीत **का अभाव**।
  - आरक्षण, अधिवास, भाषा, पहाड़ी परिषदों **पर हाल ही में राष्ट्रपति की अधिसूचनाओं (मई 2025) से असंतोष** - क्योंकि उन्होंने राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची **को संबोधित नहीं किया था**।

स्थैतिक संदर्भ

1. **छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244 और 275)**
   - असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय **क्षेत्रों को स्वायत्तता** प्रदान करता है।
   - स्वायत्त जिला परिषदों के **माध्यम से भूमि, संस्कृति और नौकरियों की सुरक्षा करता** है।
   - लद्दाख के नेताओं ने इसकी 95% आदिवासी आबादी (एसटी दर्जे) **को देखते हुए इसी तरह की सुरक्षा की मांग की**।
2. **राज्य की मांग**
   - वर्तमान यूटी स्थिति का अर्थ है विधायिका **के बिना एलजी द्वारा प्रशासन**।
   - राज्य का दर्जा **निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिक स्वायत्तता की अनुमति देगा**।
   - मिसाल: इसी तरह की मांग **दिल्ली (विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश)** में भी उठी।
3. **अनुच्छेद 370 हटाना (2019)**
   - इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के तहत लद्दाख को **भूमि और नौकरी की सुरक्षा मिलती थी**।
   - अब, भूमि बाहरी लोगों द्वारा खरीदी जा सकती है, जिससे **जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक भय बढ़ रहा है**।

शामिल मुद्दे

- **सुरक्षा आयाम: लद्दाख चीन** (पूर्वी लद्दाख एलएसी) **की सीमा से लगा हुआ है** → रणनीतिक स्थान का मतलब है कि केंद्र बहुत अधिक शक्ति हस्तांतरित करने के लिए अनिच्छुक है।
- **विकास बनाम पहचान:** स्थानीय लोगों को डर है कि **अनियंत्रित पर्यटन और औद्योगीकरण नाजुक** पारिस्थितिकी तंत्र और सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट कर देगा।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** वर्तमान में, लद्दाख में **1 लोकसभा सीट है;** बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए **2 सीटों (लेह और कारगिल)** की मांग है।
- **रोजगार:** बड़ी संख्या में **सरकारी नौकरी की रिक्तियां** खाली रहती हैं।

आगे की राह

- **संरचित संवाद:** केंद्र और लद्दाख के नेताओं के बीचनियमितसंस्थागतवार्ता।
- **अनुरूप सुरक्षा उपाय: पूर्वोत्तर** राज्यों के लिए **अनुच्छेद 371 प्रावधानों** के समान, **छठी अनुसूची के बाहर विशेष सुरक्षा** का अन्वेषण करें।
- **संतुलित विकास:** बड़े औद्योगिक प्रवेश के बजाय स्थायी पर्यटन और स्थानीय उद्यमिता **को प्रोत्साहित करना**।

- **राजनीतिक सशक्तिकरण:** विधायिका मॉडल के साथ केंद्र शासित प्रदेश **को एक मध्यवर्ती कदम के रूप में** देखें।

निष्कर्ष

लद्दाख में चल रहे विरोध प्रदर्शन **रणनीतिक केंद्रीकरण और स्वायत्तता के लिए स्थानीय आकांक्षाओं के बीच टकराव** का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि लद्दाख **राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीति के मामले में बहुत महत्व रखता है**, **भूमि**, नौकरियों और संस्कृति **की वास्तविक चिंताओं को नजरअंदाज करना** अलगाव को गहरा सकता है। नियमित **बातचीत के साथ-साथ एक संतुलित संवैधानिक समाधान**, संभवतः छठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 **सुरक्षा उपायों से प्रेरित** हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि लद्दाख **सुरक्षा और समावेशिता दोनों का एक मॉडल बन जाए**।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: संविधान की छठी अनुसूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कुछ आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान करता है।

2. यह केवल केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर लागू है।

3. छठी अनुसूची के तहत परिषदें भूमि, वन और संस्कृति पर कानून बना सकती हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(स) तीनों

(d) कोई नहीं

उत्तर : b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: लद्दाख की राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची सुरक्षा उपायों की मांग राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और स्थानीय आकांक्षाओं के बीच तनाव को दर्शाती है। चर्चा करना। **(150 शब्द)**

Page : 07: GS 3 : Science and tech / Prelims

खगोल विज्ञान ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को नया आकार देना जारी रखता है। गामा-रे फटने (जीआरबी) को बिग बैंग के बाद से सबसे शक्तिशाली घटनाओं के रूप में माना जाता था, हवाई **विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान संस्थान (आईएफए) के खगोलविदों ने** अब एक नई श्रेणी की पहचान की है: **चरम परमाणु ट्रांजिएंट (ईएनटी)।** ये दुर्लभ, बेहद शक्तिशाली विस्फोट हैं जो तब होते हैं जब **बड़े पैमाने पर तारे सुपरमैसिव ब्लैक होल से फट जाते हैं**।

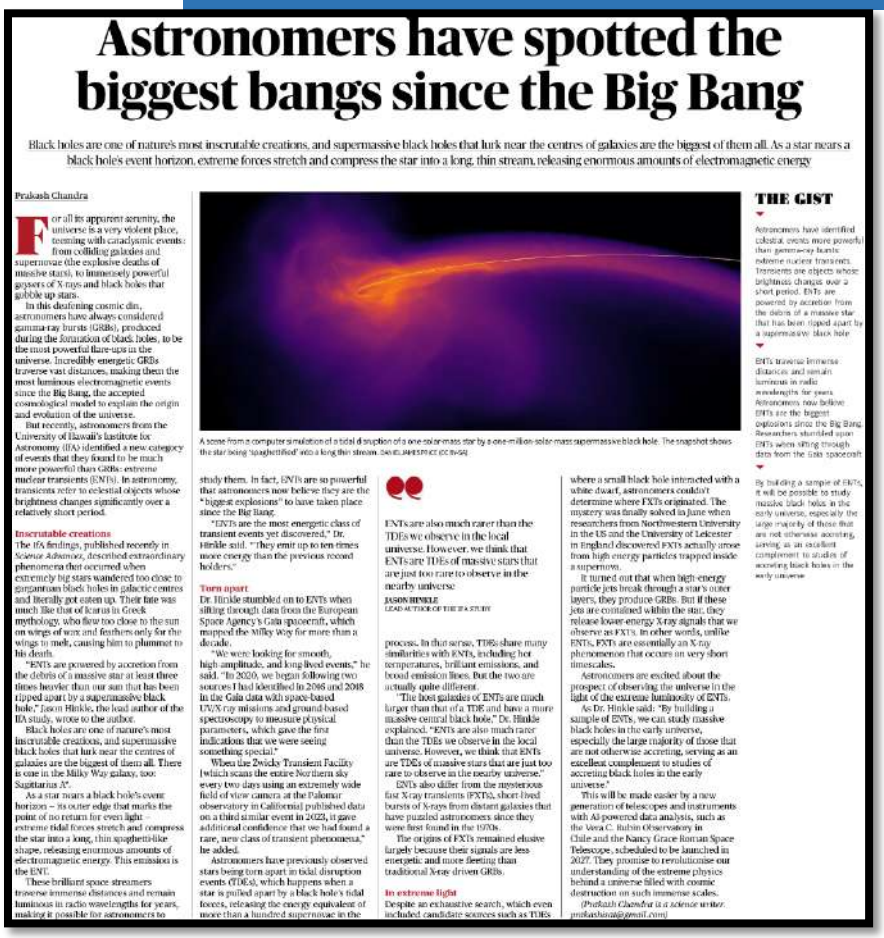

Astronomers have spotted the biggest bangs since the Big Bang

Black holes are one of nature's most inscrutable creations, and supermassive black holes that lurk near the centres of galaxies are the biggest of them all. As a star nears a black hole's event horizon, extreme forces stretch and compress the star into a long, thin stream, releasing enormous amounts of electromagnetic energy

Prakash Chandra

For all its apparent serenity, the universe is a very violent place, teeming with cataclysmic events: from colliding galaxies and supernovae (the explosive deaths of massive stars), to immensely powerful geysers of X-rays and black holes that gobble up stars.

In this deafening cosmic din, astronomers have always considered gamma-ray bursts (GRBs), produced during the formation of black holes, to be the most powerful flare-ups in the universe. Incredibly energetic GRBs traverse vast distances, making them the most luminous electromagnetic events since the Big Bang, the accepted cosmological model to explain the origin and evolution of the universe.

But recently, astronomers from the University of Hawaii's Institute for Astronomy (IfA) identified a new category of events that they found to be much more powerful than GRBs: extreme nuclear transients (ENTs). In astronomy, transients refer to celestial objects whose brightness changes significantly over a relatively short period.

Inscrutable creations

The IfA findings, published recently in *Science Advances*, described extraordinary phenomena that occurred when extremely big stars wandered too close to gargantuan black holes in galactic centres and literally got eaten up. Their fate was much like that of Icarus in Greek mythology, who flew too close to the sun on wings of wax and feathers only for the wings to melt, causing him to plummet to his death.

"ENTs are powered by accretion from the debris of a massive star at least three times heavier than our sun that has been ripped apart by a supermassive black hole," Jason Hinkle, the lead author of the IfA study, wrote to the author.

Black holes are one of nature's most inscrutable creations, and supermassive black holes that lurk near the centres of galaxies are the biggest of them all. There is one in the Milky Way galaxy, too: Sagittarius A*.

As a star nears a black hole's event horizon – its outer edge that marks the point of no return for even light – extreme tidal forces stretch and compress the star into a long, thin spaghetti-like shape, releasing enormous amounts of electromagnetic energy. This emission is the ENT.

These brilliant space streamers traverse immense distances and remain luminous in radio wavelengths for years, making it possible for astronomers to study them. In fact, ENTs are so powerful that astronomers now believe they are the "biggest explosions" to have taken place since the Big Bang.

"ENTs are the most energetic class of transient events yet discovered," Dr. Hinkle said. "They emit up to ten times more energy than the previous record holders."

Torn apart

Dr. Hinkle stumbled on to ENTs when sifting through data from the European Space Agency's Gaia spacecraft, which mapped the Milky Way for more than a decade.

"We were looking for smooth, high-amplitude, and long-lived events," he said. "In 2020, we began following two sources I had identified in 2016 and 2018 in the Gaia data with space-based UV/X-ray missions and ground-based spectroscopy to measure physical parameters, which gave the first indications that we were seeing something special."

When the Zwicky Transient Facility (which scans the entire Northern sky every two days using an extremely wide field of view camera at the Palomar observatory in California) published data on a third similar event in 2023, it gave additional confidence that we had found a rare, new class of transient phenomena," he added.

Astronomers have previously observed stars being torn apart in tidal disruption events (TDEs), which happens when a star is pulled apart by a black hole's tidal forces, releasing the energy equivalent of more than a hundred supernovae in the process. In that sense, TDEs share many similarities with ENTs, including hot temperatures, brilliant emissions, and broad emission lines. But the two are actually quite different.

"The host galaxies of ENTs are much larger than that of a TDE and have a more massive central black hole," Dr. Hinkle explained. "ENTs are also much rarer than the TDEs we observe in the local universe. However, we think that ENTs are TDEs of massive stars that are just too rare to observe in the nearby universe."

ENTs also differ from the mysterious fast X-ray transients (FXTs), short-lived bursts of X-rays from distant galaxies that have puzzled astronomers since they were first found in the 1970s.

The origins of FXTs remained elusive largely because their signals are less energetic and more fleeting than traditional X-ray driven GRBs.

In extreme light

Despite an exhaustive search, which even included candidate sources such as TDEs where a small black hole interacted with a white dwarf, astronomers couldn't determine where FXTs originated. The mystery was finally solved in June when researchers from Northwestern University in the US and the University of Leicester in England discovered FXTs actually arose from high energy particles trapped inside a supernova.

It turned out that when high-energy particle jets break through a star's outer layers, they produce GRBs. But if these jets are contained within the star, they release lower-energy X-ray signals that we observe as FXTs. In other words, unlike ENTs, FXTs are essentially an X-ray phenomenon that occurs on very short timescales.

Astronomers are excited about the prospect of observing the universe in the light of the extreme luminosity of ENTs.

As Dr. Hinkle said: "By building a sample of ENTs, we can study massive black holes in the early universe, especially the large majority of those that are not otherwise accreting, serving as an excellent complement to studies of accreting black holes in the early universe."

This will be made easier by a new generation of telescopes and instruments with AI-powered data analysis, such as the Vera C. Rubin Observatory in Chile and the Nancy Grace Roman Space Telescope, scheduled to be launched in 2027. They promise to revolutionise our understanding of the extreme physics behind a universe filled with cosmic destruction on such immense scales.

(*Prakash Chandra is a science writer. prakashiaa@gmail.com*)

A scene from a computer simulation of a tidal disruption of a one-solar-mass star by a one-million-solar-mass supermassive black hole. The snapshot shows the star being 'spaghettified' into a long thin stream. DANIEL JAMES PRICE (CC BY-SA)

> ENTs are also much rarer than the TDEs we observe in the local universe. However, we think that ENTs are TDEs of massive stars that are just too rare to observe in the nearby universe
>
> JASON HINKLE
> LEAD AUTHOR OF THE IFA STUDY

THE GIST

Astronomers have identified celestial events more powerful than gamma-ray bursts: extreme nuclear transients. Transients are objects whose brightness changes over a short period. ENTs are powered by accretion from the debris of a massive star that has been ripped apart by a supermassive black hole

ENTs traverse immense distances and remain luminous in radio wavelengths for years. Astronomers now believe ENTs are the biggest explosions since the Big Bang. Researchers stumbled upon ENTs when sifting through data from the Gaia spacecraft

By building a sample of ENTs, it will be possible to study massive black holes in the early universe, especially the large majority of those that are not otherwise accreting, serving as an excellent complement to studies of accreting black holes in the early universe

दैनिक समाचार विश्लेषण

वर्तमान संदर्भ

- **खोज:** 2020-2023 में **ESA के गैया अंतरिक्ष यान** और **ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी** से ईएनटी की पहचान की गई थी।
- **ऊर्जा उत्पादन:** ईएनटी गामा-रे फटने की तुलना में 10 गुना अधिक ऊर्जा **उत्सर्जित करते हैं**।
- **क्रियाविधि:**
  - विशाल तारे (≥3 सौर द्रव्यमान) एक **सुपरमैसिव ब्लैक होल के बहुत करीब भटकते हैं**।
  - वे "स्पेगेटीफिकेशन" **से गुजरते** हैं - ज्वारीय बलों द्वारा पतली धाराओं में फैला हुआ है।
  - मलबा ब्लैक होल में जमा हो जाता है, जिससे **वर्षों से दिखाई देने वाला** अत्यधिक विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकलता है।
- **अन्य घटनाओं के साथ तुलना:**
  - **टीडीई (ज्वारीय व्यवधान घटनाएं):** समान लेकिन छोटे सितारे/ब्लैक होल शामिल हैं; ईएनटी में बड़े तारे और बड़े ब्लैक होल शामिल होते हैं।
  - **FXTs (फास्ट एक्स-रे ट्रांजिएंट):** अल्पकालिक, कम-ऊर्जा एक्स-रे घटनाएं; अलग-अलग मूल।

स्थैतिक संदर्भ

1. **ब्लैक होल:**
   - ऐसे क्षेत्र जहां **गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता**।
   - प्रकार: तारकीय-द्रव्यमान, मध्यवर्ती, सुपरमैसिव (जैसे, आकाशगंगा में धनु A*)।
2. **घटना क्षितिज:**
   - सीमा जिसके पार कुछ भी वापस नहीं आ सकता; "कोई वापसी नहीं है।
3. **ज्वारीय बल और स्पेगेटिफिकेशन:**
   - अत्यधिक खिंचाव और संपीड़न के रूप में वस्तुएं घटना क्षितिज के करीब पहुंचती हैं।
4. **खगोल विज्ञान में क्षणिक:**
   - अल्पकालिक, उच्च चमक परिवर्तन **(नोवा, सुपरनोवा, जीआरबी, टीडीई, ईएनटी)** के साथ आकाशीय घटनाएं।

ईएनटी का महत्व

- **खगोल भौतिकी:** सुपरमैसिव ब्लैक होल **के बारे में जानकारी प्रदान करें** जो अन्यथा निष्क्रिय और अदृश्य हैं।
- **ब्रह्मांड विज्ञान:** प्रारंभिक ब्रह्मांड **की स्थितियों का अध्ययन करने में मदद करें**, जब ब्लैक होल तेजी से बढ़ रहे थे।
- **प्रौद्योगिकी:** वेरा सी. रुबिन वेधशाला **और** नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप (2027) **जैसी भविष्य की दूरबीनें** एआई-संचालित डेटा विश्लेषण **के साथ ईएनटी का पता लगाने में वृद्धि करेंगी**।
- **UPSC प्रासंगिकता:** अंतरिक्ष विज्ञानसहयोग (जैसे, **एस्ट्रोसैट, आदित्य L-1, ISRO-ESA परियोजनाएं**) मेंभारतकी रुचि को प्रदर्शित करता है।

मुद्दे और चुनौतियां

- **दुर्लभता:** ईएनटी टीडीई की तुलना में बहुत कम आम हैं, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
- **डेटा अधिभार:** आकाश सर्वेक्षण पेटाबाइट डेटा उत्पन्न करते हैं; **विश्लेषण के लिए** एआई और मशीन लर्निंग की आवश्यकता होती है।
- **अवलोकन सीमाएँ:** कई ईएनटी दूर की आकाशगंगाओं में होते हैं → केवल अगली पीढ़ी के उपकरणों से ही पता लगाया जा सकता है।

आगे की राह

- **वैश्विक सहयोग:** ईएसए, नासा, इसरो और अंतर्राष्ट्रीय वेधशालाओं के बीच डेटा साझा करना।
- **खगोल विज्ञान में एआई:** क्षणिक पहचान को स्वचालित करना।
- **भारतीय भूमिका:** इसरो के मिशनों और रुबिन और रोमन दूरबीनों **के साथ संभावित सहयोग का लाभ उठाना**।
- **सार्वजनिक विज्ञान:** ऐसी खोजों को संप्रेषित करने से **एसटीईएम जागरूकता** बढ़ती है।

निष्कर्ष

चरम परमाणु ट्रांजिएंट ब्रह्मांडीय हिंसा की सीमाओं को फिर से परिभाषित करते हैं, गामा-रे फटने को बिग बैंग के बाद से सबसे शक्तिशाली विस्फोटों के रूप में पार करते हैं। उनकी खोज से पता चलता है कि कैसे **अत्याधुनिक दूरबीन, एआई-संचालित डेटा विश्लेषण और वैश्विक सहयोग** ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल रहे हैं। यूपीएससी के लिए, ईएनटी एक अनुस्मारक हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी न केवल अंतरिक्ष के बारे में हमारे ज्ञान को गहरा करते हैं बल्कि **मानव जिज्ञासा और अन्वेषण की सीमाओं का भी प्रतीक हैं**।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : निम्नलिखित खगोलीय घटनाओं पर विचार कीजिए:

1. गामा-रे बर्स्ट (जीआरबी)

2. ज्वारीय व्यवधान घटनाएँ (TDEs)

3. चरम परमाणु ट्रांजिएंट (ईएनटी)

उपरोक्त में से कौन-सा/से सुपरमैसिव ब्लैक होल का उपभोग करने वाले तारों से जुड़ा है?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: बी)

UPSC Mains Practice Question

Ques :एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट (ENTs) को बिग बैंग के बाद से सबसे शक्तिशाली विस्फोट के रूप में वर्णित किया गया है। बताएं कि उनका अध्ययन हमें सुपरमैसिव ब्लैक होल और प्रारंभिक ब्रह्मांड के विकास को समझने में कैसे मदद कर सकता है। **(150 शब्द)**

दैनिक समाचार विश्लेषण

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन ने नए**आवेदकों के लिए एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाकर 100,000 डॉलर** करने का फैसला किया है । एच-1बी वीजा प्राप्तकर्ताओं में भारतीय नागरिकों की संख्या 70 प्रतिशत से अधिक है, इस नीति में बदलाव का सीधा असर भारत के **तकनीकी कार्यबल, परिवारों और आईटी सेवा उद्योग** पर पड़ता है। यह **कुशल प्रवासन, संरक्षणवाद और अमेरिकी नौकरियों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की भारत की आवश्यकता** के बारे में व्यापक सवाल भी उठाता है।

H-1B, maybe

India's tech workers must reduce their reliance on U.S. jobs

President Donald Trump's decision to charge new applicants for the H-1B highly skilled non-immigrant visa $100,000, nearly six times the current fee, has caused widespread consternation that not only might the lives of tens of thousands of potential visa applicants in the tech space be impacted, leading to "humanitarian consequences" for families, as mentioned by India's Ministry of External Affairs, but there will also be widespread disruption among major tech companies in the U.S. that rely on hiring skilled workers under this visa. While the number of visas issued in this category has been capped at 85,000 per year since 2004, and allocations are decided through a lottery, reports based on U.S. Citizenship and Immigration Services data suggest that applications for the upcoming fiscal year have dropped to a four-year low of nearly 3,59,000. Indian nationals typically account for 71% of these visas, yet data also suggest that close to 60% of these visa recipients earn less than $100,000, which, over the longer term, implies that their employers may find it harder to justify hiring such specialised workers from abroad. The External Affairs Ministry's response to the White House action included a reiteration of the fact that "Skilled talent mobility and exchanges have contributed enormously to technology development, innovation, economic growth, competitiveness and wealth creation in the U.S. and India", yet there is limited scope for South Block to apply pressure, diplomatic or political, to get the policy reversed.

However, the fallout for Indian citizens can be contained if there is a proactive approach by the Government to bolster India's infrastructure and undertake necessary reforms to improve the prospects for the Indian tech industry to make even greater strides than it has done so far. This might be achieved by capitalising on opportunities to develop new capabilities in the Artificial Intelligence space and exploring new markets across Asia, including China and Russia, and in parts of Europe, where the transatlantic contagion of nativist protectionism has not yet found willing takers. While the Trump order is set to expire within a year, there is no guarantee that it would not be extended, making it all the more pertinent for policymakers in India to evolve a long-term plan to reduce reliance of Indian tech workers on the shrinking pool of job opportunities in the U.S. economy. As India and other countries adjust to this new reality of the hostility of the Trump White House to welcoming future innovators, job-creators, and tax-payers to their shores, it is the U.S. rather than other nations that will suffer a shortage of scientific and engineering prowess to fuel economic progress.

वर्तमान संदर्भ

- **शुल्क वृद्धि:** $ 100,000 (मौजूदा स्तरों से लगभग 6 गुना वृद्धि)।
- **कैप:** वार्षिक सीमा बनी हुई है **85,000 वीजा** (2004 से), लॉटरी के माध्यम से आवंटित.
- **आवेदन रुझान:** 2025 चक्र में **आवेदन गिरकर 3.59 लाख (4 वर्ष का निम्नतम) हो गया**।
- **भारत का हिस्सा:** ~71% प्राप्तकर्ता भारतीय नागरिक हैं; **60% $ 100,000 < कमाते हैं**, जिससे अमेरिकी नियोक्ताओं के लिए लागत-लाभ संबंधी चिंताएं बढ़ जाती हैं।
- **राजनयिक प्रतिक्रिया:** भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी नवाचार में भारतीय तकनीकी प्रतिभा के योगदान पर प्रकाश डाला, लेकिन नीति को उलटने के लिए लाभ सीमित है।

स्थैतिक संदर्भ

1. **एच-1बी वीजा:**
   - विशेष व्यवसायों (तकनीक, इंजीनियरिंग, चिकित्सा) में कुशल श्रमिकों के लिए गैर-आप्रवासी वीजा।
   - शुरुआत में अमेरिकी कार्यबल में **कौशल अंतराल को** भरने के लिए बनाया गया था।
2. **प्रतिभा पलायन और प्रतिभा लाभ:**
   - भारत लंबे समय से अमेरिका के लिए तकनीकी प्रतिभाओं के प्रतिभा पलायन का सामना कर रहा है
   - हाल की नीतियां + भारत के आईटी उद्योग का उदय धीरे-धीरे ब्रेन गेन **(प्रतिभा वापसी, दूरस्थ कार्य)** की ओर बदलाव →।
3. **संरक्षणवादबनामवैश्वीकरण:**
   - अमेरिकी कदम **मूलवादी, संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों को दर्शाता है**, जो वैश्वीकरण में श्रम के मुक्त आंदोलन के सिद्धांतों के साथटकरारहाहै।

भारत के लिए निहितार्थ

- **अल्पावधिक:**
  - संभावित प्रवासियों के परिवारों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है।
  - भारतीय आईटी कंपनियों को राजस्व में गिरावट **और परिचालन लागत में वृद्धि** का सामना करना पड़ सकता है।
  - सिलिकॉन वैली के लिए प्रतिभा पाइपलाइन बाधित।
- **दीर्घावधिक:**
  - भारत के लिए **घरेलू तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र** (एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा) बनाने का अवसर।
  - निर्भरता में विविधता लाने के लिए **एशिया, यूरोप, अफ्रीका में नए बाजारों** का अन्वेषण करें।

- आईटी में **दूरस्थ कार्य मॉडल और वैश्विक फ्रीलांसिंग** पर जोर दें।

भारत के लिए आगे की राह

1. **नीतिगत सुधार:** भारत के **डिजिटल बुनियादी ढांचे, व्यापार करने में आसानी** और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।
2. **अपस्किलिंग:** मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए **एआई, सेमीकंडक्टर डिजाइन, क्लाउड, ग्रीन टेक कौशल** में बड़े पैमाने पर निवेश।
3. **वैश्विक रणनीति:** अमेरिका से परे द्विपक्षीय प्रतिभा गतिशीलता साझेदारी **बनाएं** (उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ)।
4. **प्रवासी भारतीयों का लाभ उठाएं:** विदेशों में भारतीय मूल के तकनीकी नेताओं को **भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें**।

निष्कर्ष

अमेरिकी वीजा शुल्क में वृद्धि अपने **कुशल पेशेवरों के लिए एक देश के नौकरी बाजार पर भारत की अत्यधिक निर्भरता के जोखिम को रेखांकित करती है**। जबकि अमेरिका को लंबे समय में प्रतिभा की कमी का सामना करना पड़ सकता है, भारत के लिए तत्काल चुनौती अपनी **तकनीकी रणनीति को फिर से व्यवस्थित** करना है। बाजारों में विविधता लाकर, घरेलू नवाचार को बढ़ावा देकर और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देकर, भारत इस चुनौती को एक अवसर में बदल सकता है - अमेरिकी वीजा पर निर्भरता को कम करके और खुद को **प्रौद्योगिकी और नवाचार के वैश्विक केंद्र** के रूप में स्थापित कर सकता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: एच-1बी वीजा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।

2. 2004 से एच-1बी वीजा के लिए वार्षिक सीमा 85,000 तय की गई है।

3. एच-1बी प्राप्तकर्ताओं में भारतीय नागरिकों की संख्या 25 प्रतिशत से भी कम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

UPSC Mains Practice Question

दैनिक समाचार विश्लेषण

प्रश्न: एच-1बी वीजा शुल्क वृद्धि जैसी संरक्षणवादी नीतियां भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, इसका गंभीर विश्लेषण करें। इस संदर्भ में, भारत अपने घरेलू नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अपने द्वारा अपनाए जा सकने वाले उपायों पर प्रकाश डालता है। **(150 शब्द)**

Page : 08 Editorial Analysis

Can timelines be fixed for Governors?

Can the Governor withhold assent to a Bill passed by the State legislature based on his own discretion? Why has the Centre said that courts cannot prescribe a timeline for Governors/President to decide on a Bill? What have Opposition-rule States said on the matter?

EXPLAINER

Rangarajan R.

The story so far:

The Supreme Court is currently hearing a Presidential reference made in May 2025 that has sought the opinion of the Court on 14 questions, primarily surrounding the interpretation of Articles 200 and 201 of the Constitution.

What is the current reference?

The current reference is a result of a Supreme Court judgment in April 2025 (*The State of Tamil Nadu versus the Governor of Tamil Nadu & Anr*) that had specified timelines for Governors and the President to act on Bills passed by State legislatures. It had held that if the Governor was to withhold assent or reserve the Bill for consideration of the President, contrary to the advice of the State Council of Ministers, he/she should do so within a period of three months. It further held that if a Bill for which assent has been withheld is again passed by the State legislature, the Governor shall assent to such Bill. It had prescribed a timeline of three months for the President to decide on State Bills reserved for his/her consideration. The court had also held that decisions by Governors and the President on such Bills, including delays beyond the prescribed timelines, will be subject to judicial review.

The government has raised questions regarding the authority of the Court to prescribe timelines when they are not specified in the Constitution.

What does the Constitution say?

Article 200 of the Constitution lays down that when a Bill, passed by a State Legislature, is presented to the Governor for his/her assent, he/she has four alternatives: (a) may give assent to the Bill (b) may withhold assent to the Bill, that is, reject the Bill in which case the Bill fails to become law; (c) may return the Bill for reconsideration of the State Legislature; or (d) may reserve the Bill for the consideration of the President.

As held by the Supreme Court in various cases including the *Shamsher Singh case* (1974), the Governor does not exercise his/her discretionary powers while withholding assent for a Bill. He/she is required to act as per the advice of the Council of Ministers. The return of any Bill to the State Legislature for reconsideration is also to be done based on ministerial advice. As explained in the Constituent Assembly by T.T. Krishnamachari, this may be done if the Government feels that the Bill needs modifications. The Governor shall assent to such a Bill if it is passed again by the State Legislature.

As far as reserving any Bill for consideration of the President, the Governor must reserve certain Bills like those which reduce the powers of the High Court. He/she may reserve certain Bills based on the advice of the Council of Ministers like those that relate to a subject enumerated in the Concurrent List, to ensure operation of its provisions despite repugnancy to a Union Law. It is only under rare circumstances that the Governor may exercise his/her discretion and reserve a Bill where he/she feels that the provisions of the Bill contravene any of the provisions of the Constitution and therefore, reserve it for the consideration of the President.

The Constitution does not lay down any time limit within which the Governor is required to make a decision with respect to any Bill presented for his/her assent. The main part of Article 200 states that once a Bill is presented to the Governor, he/she 'shall' declare that he/she assents to the Bill or withholds assent or reserves the Bill for consideration of the President. The proviso to the article adds that the Governor may 'as soon as possible' return the Bill for reconsideration of the State legislature.

What are the recommendations?

The Sarkaria Commission (1987) had stated that only the reservation of Bills for consideration of the President, that too under rare cases of patent unconstitutionality, can be implied as a discretionary power of the Governor. Apart from such exceptional cases, the Governor must discharge his functions under Article 200 as per the advice of Ministers. It further recommended that the President (Central Government) should dispose of such Bills within a maximum period of six months. The Punchhi Commission (2010) had recommended that the Governor should take a decision with respect to a Bill presented for his/her assent within a period of six months.

What are the arguments?

Article 163(1) of the Constitution requires the Governor to act as per the advice of the Council of Ministers except in so far as he/she is required by or under the Constitution to act as per his/her discretion. Article 163(2) further provides that if any question arises on whether the matter is a matter which the Governor is required to act as per his/her discretion, the decision of the Governor in such cases shall be final and shall not be called into question.

The Centre has argued that the Governor enjoys discretion as per the above Article which cannot be inquired into by the courts and consequently no timelines can be fixed. It also raised objections to the three-month timeframe that has been stipulated for the President to decide on Bills which have been reserved. Article 201 that deals with this matter does not stipulate any timeline. The Centre has maintained that any issues between the elected government in a State, the Governor and the President need to be resolved politically within the framework of the Constitution and that the courts cannot be an adjudicator for every such impasse.

However, Opposition-ruled States have argued that the Governors in such States have been selectively delaying assent or reserving Bills, against the advice of the Council of Ministers, for the consideration of the President. They have argued that such deliberate delays cannot be termed as discretion and that it disrespects the popular mandate of the people of the State.

What should be the way forward?

All the issues stated above are in the nature of symptoms. The underlying disease that has plagued our federal set up has been the politicisation of the gubernatorial post. Many political leaders starting from C.N. Annadurai to Nitish Kumar have called for the abolition of the Governor's post in the past. However, as per our Constitutional scheme, there is a need for a nominal head of the State executive just like the President for the Union executive.

Nevertheless, federalism is also a basic feature of our Constitution and the Governor's office should not undermine the powers of popularly elected governments at the States.

The Court usually exercises restraint while stipulating timelines for action by constitutional authorities where none is provided in the Constitution. However, when there are unreasonable delays, the Court has stipulated timelines in the past like in *K. M. Singh case* (2020) where it laid down a three-month timeframe for Speakers to decide on the Tenth Schedule disqualification.

The Supreme Court has purposively interpreted the words in Article 200 in its judgment in April 2025. It has interpreted that the main part of Article 200 uses the words 'Governor shall' and hence it is not a discretionary power. It relied on its own past judgments including the *Nabam Rebia case* (2016), the recommendations of various commissions as well as the Office Memorandum of the Home Ministry in 2016 to prescribe the timeline of three months for actions by Governors and the President.

The Centre and the Governors should follow the timeline prescribed by the April 2025 judgment to uphold democratic and federal principles. Hopefully, the opinion of the Supreme Court in the Presidential reference would also reiterate this position.

Rangarajan. R is a former IAS officer and author of 'Courseware on Polity Simplified.' He currently trains at Officers IAS academy. Views expressed are personal.

New rules: Tamil Nadu Governor R.N. Ravi welcomed by Chief Minister M.K. Stalin during the Republic Day celebrations in Chennai on January 26. PTI

THE GIST

Article 200 of the Constitution lays down that when a Bill, passed by a State Legislature, is presented to the Governor for his/her assent, he/she has four alternatives: (a) may give assent to the Bill (b) may withhold assent to the Bill, that is, reject the Bill in which case the Bill fails to become law; (c) may return the Bill for reconsideration of the State Legislature; or (d) may reserve the Bill for the consideration of the President.

Article 163(1) of the Constitution requires the Governor to act as per the advice of the Council of Ministers except in so far as he/she is required by or under the Constitution to act as per his/her discretion.

Opposition-ruled States have argued that the Governors in such States have been selectively delaying assent or reserving Bills, against the advice of the Council of Ministers.

GS. Paper 02- भारतीयराजनीति

UPSC Mains Practice Question: क्याराज्यपालोंके लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समयसीमा तय की जा सकती है? भारत में अनुच्छेद 200, 201 और संघीय सिद्धांतों के आलोक में चर्चा करें।(150 शब्द)

दैनिक समाचार विश्लेषण

संदर्भ:

भारत में राज्यपाल का कार्यालय, जिसे संवैधानिक रूप से **राज्य के नाममात्र के प्रमुख के रूप में डिज़ाइन किया गया है**, अक्सर खुद को संघीय तनाव के केंद्र में पाता है, खासकर जब राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को रोक दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है। **अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले** और उसके बाद राष्ट्रपति **के संदर्भ ने इस** बात पर बहस फिर से शुरू कर दी है कि क्या **संविधान के अनुच्छेद 200 और 201** के तहत राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए **समयसीमा तय की जा सकती** है ।

संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 200:** जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह यह कर सकता है:
    1. सहमति दें
    2. **सहमति रोकें** (अस्वीकार)
    3. **विधेयक को पुनर्विचार के लिए** लौटाएं
    4. **विधेयक को** राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखें
- **अनुच्छेद 201:** राज्यपालों द्वारा आरक्षित विधेयकों के लिए **राष्ट्रपति की सहमति को** नियंत्रित करता है।
- **अनुच्छेद 163:** राज्यपालों को मंत्रिस्तरीय सलाह पर **कार्य करने की आवश्यकता होती** है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां विवेक अनिवार्य है।

प्रमुख बिंदु:

- आम तौर पर, **राज्यपाल संभावित असंवैधानिकता** या उच्च न्यायालयों को प्रभावित करने वाले कुछ विधेयकों **जैसे दुर्लभ मामलों को छोड़कर व्यक्तिगत** विवेक का प्रयोग नहीं करता है।
- संविधान में **राज्यपालों/राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए** समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और आयोग की सिफारिशें

- **शमशेर सिंह केस (1974):** राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए; विवेकाधीन शक्तियां सीमित हैं।
- **अप्रैल 2025 का फैसला (TN बनाम गवर्नर):**
    - राज्यपाल के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए **3 महीने की समयसीमा** निर्दिष्ट की गई है।
    - यदि कोई विधेयक विधायिका द्वारा फिर से पारित किया जाता है, तो राज्यपाल को इसकी अनुमति देनी होगी।
    - आरक्षित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति को 3 महीने की समय-सीमा का भी सुझाव दिया गया है।
- **सरकारियाआयोग (1987):**केवल**दुर्लभअसंवैधानिक विधेयकों को** राज्यपाल के विवेक पर आरक्षित किया जा सकता है; राष्ट्रपति को 6 महीने के भीतर निपटान करना होगा।
- **पुंछीआयोग (2010):** राज्यपालको 6 महीने के भीतर विधेयकों पर कार्रवाई करने की **सिफारिश की**।

समयसीमा के पक्ष और विपक्ष में तर्क

केंद्र/राज्यपाल-पक्ष:

- अनुच्छेद 163 (2) **विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है**; अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।
- संविधान में स्पष्ट समयसीमा का अभाव है; न्यायिक थोपने से **कार्यपालिका के विवेकाधिकार का हनन** हो सकता है।
- राजनीतिक मुद्दों को **संवैधानिक ढांचे के भीतर हल किया जाना चाहिए**, न कि अदालतों द्वारा।

विपक्ष/राज्य पक्ष:

- विपक्ष शासित राज्यों के राज्यपालों ने **चुनिंदा रूप से विधेयकों में देरी** की है।
- इस तरह की देरी लोकप्रिय **जनादेश** और संघवाद को कमजोर करती है।
- समयसीमा निर्वाचित सरकारों के लिए **जवाबदेही** और सम्मान सुनिश्चित करती है।

दांव पर लगे मुद्दे

1. **संघवाद:** केंद्र, राज्यपाल और राज्य विधायिका **के बीच संतुलन की रक्षा करना**।
2. **लोकतांत्रिक जनादेश:** निर्वाचित सरकारों को बाधित करने के लिए गवर्नर पद के दुरुपयोग को रोकना।
3. **न्यायिक समीक्षा:** अदालतें संयम बरतती हैं, लेकिन हस्तक्षेप करती हैं जब **अनुचित देरी संवैधानिक** शासन को खतरे में डालती है (उदाहरण के लिए, केएम सिंह, 2020)।
4. **राज्यपालपदकाराजनीतिकरण:**सुधारोंकीमांग की गई है, लेकिन **उन्मूलन संवैधानिक रूप से अव्यावहारिक है**।

आगे की राह

- राज्यपालों को **लोकतांत्रिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए** अप्रैल 2025 की सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा का पालन करना चाहिए।
- केंद्रोंऔरराज्यसरकारोंको**राजनीतिकहेरफेरसेबचते हुए** संघीय सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए।
- अदालतें **कार्यकारी विवेक का अतिक्रमण किए बिना अनुचित देरी को रोकने के लिए** चुनिंदा रूप से हस्तक्षेप कर सकती हैं।
- राज्यपाल के कार्यालय के राजनीतिकरण को कम करने के लिए **संवैधानिक सुधारों** या दिशानिर्देशों पर विचार।

निष्कर्ष

राज्यपाल की सहमति शक्तियां विवेकाधीन के बजाय **काफी हद तक मंत्रिस्तरीय** हैं । अप्रैल 2025 का फैसला संवैधानिक पद को परेशान किए बिना **संघवाद और लोकतांत्रिक जनादेश की रक्षा करने के न्यायिक प्रयास** को दर्शाता है । जबकि अनुच्छेद 163 सीमित विवेक की अनुमति देता है, सहमति **के लिए समयसीमा** जवाबदेही को मजबूत करती है और शक्ति के दुरुपयोग को रोकती है, यह सुनिश्चित करती है कि निर्वाचित सरकारें बिना किसी बाधा के कामकरसकतीहैं।

दैनिक समाचार विश्लेषण

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

प्रारम्भ बैच (PT BATCH 2026)

- DURATION : 7 MONTH
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS - PT ORIENTED PYQ'S
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- DAILY THE HINDU ANALYSIS
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES
- DOUBT SESSIONS

ONE TIME PAYMENT
RS 17,500/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 20,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

सफलता बैच (Pre 2 Interview)

- DURATION : 1 YEAR
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS - (PT + MAINS) WITH PYQ'S
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- DAILY THE HINDU ANALYSIS
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES
- DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES (WEEKLY)

ONE TIME PAYMENT
RS 30,000/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 35,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 4TH OCT 2025
आधार बैच (Aadhaar Batch)
DURATION : 2 YEARS
DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
BOOKS – PT ORIENTED PYQ'S + MAINS
MAGZINE : HARD + SOFT COPY
NCERT FOUNDATION
SEPERATE PT & MAINS QUESTION SOLVING CLASSES
TEST SERIES WITH DISCUSSION
MENTORSHIP (PERSONALISED)
BILINGUAL CLASSES & DOUBT SESSIONS
MAINS ANSWER WRITING CLASSES
ONE TIME PAYMENT
RS 50,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 55,000/-
Register Now
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

दैनिक समाचार विश्लेषण

Nitin sir classes

Know your daily

CLASSES

TIME TABLE FOR DAILY CLASSES

- 07:30 PM - THE HINDU ANALYSIS
- 09:00 PM - Daily Q & A Session (PT + Mains)

SUBSCRIBE

HTTPS://T.ME/NITIN KUMAR (PSIR)

WWW.NITINSIRCLASSES.COM

दैनिक समाचार विश्लेषण

Follow More

- **Phone Number : - 9999154587**
- **Website : - https://nitinsirclasses.com/**
- **Email : - k.nitinca@gmail.com**
- **Youtube : -https://youtube.com/@nitinsirclasses8314?si=a7Wf6zaTC5Px08Nf**
- **Instagram :- https://www.instagram.com/k.nitinca?igsh=MTVxeXgxNGJyajN3aw==**
- **Facebook : - https://www.facebook.com/share/19JbpGvTgM/?mibextid=qi2Omg**
- **Telegram : - https://t.me/+ebUFssPR83NhNmJl**